विश्व व्यापार संगठन
अबूधाबी से आगे कैमरून तक की यात्रा?

अबूधाबी में 13वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हाल ही में 1 मार्च, 2024 की आधी रात को संपन्न हुआ है और घोषणा अगले दिन, व्यावहारिक रूप से 26–29 फरवरी, 2024 की निर्धारित तिथि के 2 दिन बाद जारी की गई थी। सम्मेलन ख़त्म होने की कगार पर था, क्योंकि सदस्य देश चार सबसे विवादास्पद और संदिग्ध मुद्दों में से किसी पर भी आम सहमति बनाने में असमर्थ थे। हालाँकि वे अंततः डिजिटल उत्पादों या ई–ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने के लिए स्थगन के विस्तार को मंजूरी देकर एक सकारात्मक नोट पर सहमत हुए, जिसे 1998 के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अस्थायी आधार पर छूट दी गई थी।

ये चार विवादास्पद मुद्दे थे– 1. मछली पालन पर सब्सिडी ख़त्म करना, 2. निवेश सुविधा विकास समझौते (आईएफडीए) को अपनाना, 3. खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) तथा 4. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक लगाना।

यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 15–04–1994 को हुई थी और इसने अपने अस्तित्व के लगभग 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर में दो नए सदस्यों के शामिल होने के साथ इसके 166 सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश मिलकर लगभग 97 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आइए, उपरोक्त चार विवादास्पद मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करें। उन्हें संदिग्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर तो वे आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनका इरादा और डिज़ाइन विकासशील देशों को वंचित करना और उनकी संप्रभुता का अतिक्रमण करना है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का एजेंडा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएं। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों की हमेशा

डिब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली में सुधार होगा और अगली बैठक जो केमरून में होगी, तब तक इसे प्रजातांत्रिक और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जायेगा।
– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

Total Estimated Agricultural Supports in 2019

Ranked by Spend as a % of Gross Farm Revenue		Ranked by Total Spend (% Gross Farm Revenue)	
1. NORWAY - $3.03 billion	57.6%	1. CHINA (12.1%)	$185.9 billion
2. ICELAND - $223.2 million	54.6%	2. EUROPEAN UNION (19.0%)	$101.3 billion
3. SWITZERLAND - $6.16 billion	47.4%	3. UNITED STATES (12.1%)	$48.9 billion
4. KOREA - $20.8 billion	46.1%	4. JAPAN (41.3%)	$37.6 billion
5. JAPAN - $37.6 billion	41.3%	5. INDONESIA (23.3%)	$29.4 billion
6. PHILIPPINES - $7.3 billion	27.1%	6. KOREA (46.1%)	$20.8 billion
7. INDONESIA - $29.4 billion	23.3%	7. RUSSIA (9.2%)	$7.9 billion
8. EUROPEAN UNION - $101.3 billion	19.0%	8. PHILIPPINES (27.1%)	$7.3 billion
9. ISRAEL - $1.5 billion	17.4%	9. TURKEY (13.5%)	$6.7 billion
10. TURKEY - $6.7 billion	13.5%	10. SWITZERLAND (47.4%)	$6.2 billion

SOURCE: OECD Data, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020 Reference Tables.

से यह चिंता रही है कि विकसित देशों द्वारा अपने कृषि–व्यवसाय समूहों को दी जाने वाली व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी बंद की जानी चाहिए, लेकिन इसके बजाए वे विकासशील देशों से खाद्य सुरक्षा के लिए उनकी वैध मांगों को मान्यता दिए बिना अपनी सब्सिडी में कटौती करने के लिए कह रहे हैं और गरीब किसानों की आजीविका के बारे में बुनियादी अधिकार। विकासशील देशों की उनके कृषि उत्पादन के 10 प्रतिशत के बराबर घरेलू समर्थन निर्धारित करने के लिए बाहरी संदर्भ मूल्य (ईआरपी) के आधार वर्ष 1986–88 को बदलने की पुरानी पोषित मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है और विकसित देशों ने नाजायज सब्सिडी को शामिल करना जारी रखा है।

ग्रीन बॉक्स को एम्बर बॉक्स के दायरे से बाहर होने का आरोप लगाया गया है, जो उनके कृषि उत्पादन के 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन है। इसी तरह भौगोलिक संकेत रजिस्टर में दार्जिलिंग चाय जैसे उत्पादों का विस्तार करने की विकासशील देशों की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पारंपरिक ज्ञान, जैव–विविधता का मुद्दा चर्चा के एजेंडे से बाहर है। प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कुछ नये मुद्दे लादे जाते हैं। कैनकुन में 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में निवेश के मुद्दों को हटाने के लिए जोरदार तर्क दिया गया और अंततः व्यापार सुविधा को छोड़कर सिंगापुर के सभी मुद्दों को डब्ल्यूटीओ एजेंडा से बाहर कर दिया गया, जिसे गारंटी के बदले में 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (बाली) में अपनाया गया था।

गरीब किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान प्रदान करना, लेकिन उस मुद्दे को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस 13वीं एमसी के दौरान भी इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी गई और पूरी चर्चा निवेश और ई–कॉमर्स के इर्द–गिर्द ही रही।

मत्स्य पालन के पहले मुद्दे पर 2022 में 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की थी कि अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने पर सब्सिडी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा गहरे पानी में मछली पकड़ने पर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर मछली पकड़ने को विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) लाभ देकर छोटे मछुआरों के लिए विशेष रूप से बाहर रखा जाना चाहिए।

हालाँकि विकसित देश विकासशील देशों के छोटे मछुआरों को

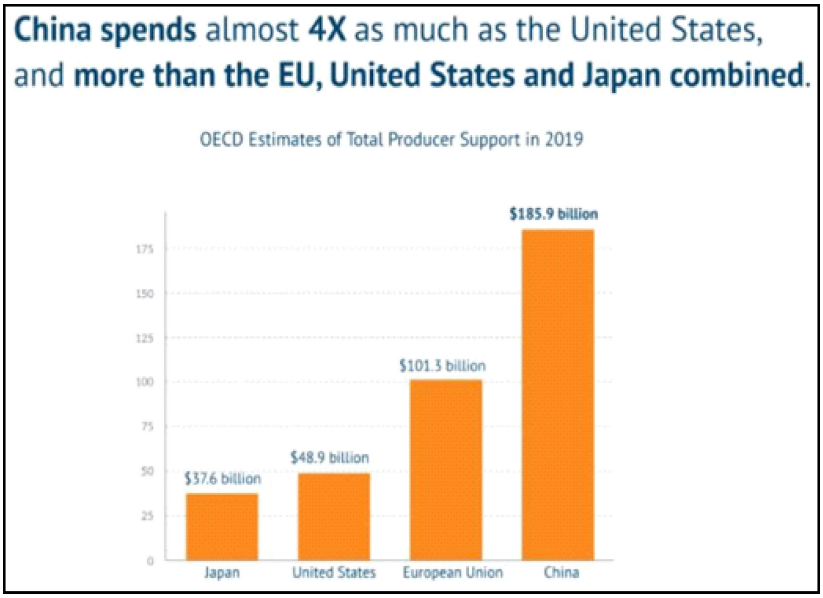

डिजिटल व्यापार के कुछ आँकड़े (2023)

वैश्विक:

- ई–कॉमर्स बिक्री: 5.2 ट्रिलियन डॉलर (2023)
- ई–कॉमर्स बिक्री में वृद्धि: 13.7 प्रतिशत (2022–2023)
- ई–कॉमर्स उपयोगकर्ता: 4.9 बिलियन (2023)
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य: 11.5 ट्रिलियन डालर (2023)

भारत:

- ई–कॉमर्स बिक्री: 120 बिलियन डालर (2023)
- ई–कॉमर्स बिक्री में वृद्धि: 30 प्रतिशत (2022–2023)
- ई–कॉमर्स उपयोगकर्ता: 650 मिलियन (2023)
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य: 250 बिलियन डालर (2023)

अन्य:

- मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता: 5. 3 बिलियन (2023)
- स्मार्टफोन उपयोगकर्ता: 6.6 बिलियन (2023)
- सोशल मीडिया उपयोगकर्ता: 4.7 बिलियन (2023)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आँकड़े अनुमान हैं और वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है।

Source of Data compilation:
- https://www.statista.com/
- https://www.weforum.org/

दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने पर ज़ोर दे रहे थे और इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

चीन और कुछ अन्य देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एफडीआई के मुक्त प्रवाह के लिए पिछले दरवाजे के माध्यम से बहुपक्षीय समझौते के रूप में विकास के नाम पर निवेश सुविधा समझौते को लाना चाहते थे और इस तरह मेजबान देश के लिए नीतिगत स्थान को कम करना चाहते थे और यहां तक कि

राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर भी। संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा की कूटनीति अन्य सदस्यों को समझाने में विफल रही और भारत ने व्यावहारिक रूप से अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया क्योंकि डब्ल्यूटीओ को सभी सदस्यों की स्पष्ट सहमति के साथ काम करना पड़ता है और निवेश एक व्यापार मुद्दा है।

कृषि के मुद्दे ने अपनी प्राथमिकता खो दी, क्योंकि विकसित देश सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे का स्थायी समाधान देने के मूड में नहीं थे और चर्चा के अभाव में मामला कार्यान्वयन से लंबित रहा। ओईसीडी की 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के 54 सदस्य देशों के लिए 2019–21 में कृषि क्षेत्र को कुल समर्थन 817 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच गया, जो 2018–20 के लिए रिपोर्ट किए गए 720 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13 प्रतिशत अधिक है।

सबसे अहम बहस ई–कॉमर्स और ई–ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने पर लगी रोक खत्म करने के मुद्दे पर हुई।

भारत सहित कई देशों ने ई–कॉमर्स पर मोराटोरियम के विस्तार का विरोध किया था। इन देशों का तर्क था कि मोराटोरियम डिजिटल व्यापार के विकास में बाधा डालता है और विकसित देशों को अनुचित लाभ देता है। विरोध करने वाले देशों का मुख्य तर्क यह था कि मोराटोरियम विकसित देशों को अपनी डिजिटल कंपनियों को विकासशील देशों के बाजारों में प्रवेश करने और उन पर हावी होने का अनुचित लाभ देता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि मोराटोरियम विकासशील देशों को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और डिजिटल व्यापार से लाभ उठाने से रोकता है।

भारत ने विशेष रूप से मोराटोरियम का विरोध किया क्योंकि यह डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को लागू करने की अपनी क्षमता को सीमित करता है। भारत चाहता है कि डिजिटल कंपनियां अपने डेटा को भारत में स्टोर करें, ताकि सरकार डेटा तक पहुंच और उसका उपयोग कर सके।

मंत्री स्तरीय बैठक को एक सार्थक रूप प्रदान करने के लिये एक सहमति बनी कि 14वीं बैठक तक मॉरटॉरीयम को बढ़ाया जाता है, पर किसी भी हालत में अंतिम तिथि 31–03–2026 रहेगी। आशा है डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली में सुधार होगा और अगली बैठक जो केमरून में होगी, तब तक इसे प्रजातांत्रिक और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जायेगा। ❑❑